www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 118 | जौनपुर शुक्रवार, 12 दिसम्बर 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

आतंकी फंडिंग मामले में ईडी और महाराष्ट्र एटीएस की कार्रवाई

मुंबई, (एजेंसी)। ईडी और महाराष्ट्र आतंकवाद–रोधी दस्ता ने संदिग्ध आतंकवादी फंडिंग के मामले में गुरुवार को ठाणे जिले के पडघा में संयुक्त छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि भिवंडी के पडघा में गुरुवार की सुबह से छापेमारी जारी है। यह कार्रवाई पहले के अभियानों के आधार पर की जा रही है। पहले पडघा के बोरिवली गांव में छापेमारी गई थी। कई संदिग्धों के घरों की तलाशी ली जा रही है और ईडी संदिग्ध पैसे के लेन–देन की जांच कर रही है। इसमें एटीसी केंद्रीय जांच एजेंसी का सहयोग कर रही है। इस साल जून में, ञ्जस् ने ठाणे ग्रामीण पुलिस के साथ मिलकर पादघा के बोरिवली में 22 लोगों के घरों पर बड़ी छापेमारी की थी। इनमें स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के पूर्व पदाधिकारी साकिब नचन और अन्य संदिग्ध सदस्य तथा प्रतिबंधित संगठन के समर्थक शामिल थे। अधिकारी ने बताया कि एटीएस ने उस समय 19 मोबाइल फोन और कट्टरपंथी गतिविधियों तथा दस्तावेजों से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री जब्त की थी। दो साल पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आतंकवादियों से जुड़ी गतिविधियों के मामले भी पडघा में छापेमारी की थी। साकिब नचन को एनआईए ने पडघा से गिरफ्तार किया था। इस साल जून में दिल्ली के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी।

किसानों के लिए नायब सिंह सैनी का बड़ा ऐलान

चंडीगढ़, (एजेंसी)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) से जुड़े किसानों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए बकाया अतिदेय ऋणों के निपटान के लिए एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की। यह योजना 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगी। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री बुधवार को सिविल सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में बजट सत्र 2025–26 में किसानों की पैक्स की तरफ बकाया अतिदेय ऋण के निपटान हेतु योजना लाने की घोषणा की थी। इसी के अनुरूप आज यह योजना लाई गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पैक्स से ऋण लेने वाले किसान यदि अपने ऋण की मूल राशि समिति के खातों में जमा करवाते हैं, तो उनका पूरा बकाया ब्याज माफ किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के 6,81,182 किसानों व गरीब मजदूरों का 2,266 करोड़ रुपये का ब्याज माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना उन सभी कर्जदार किसानों के लिए है, जिन्होंने फसली ऋण, काश्तकार ऋण या दुकानदारी के लिए ऋण लिया है, जो 30 सितंबर, 2024 को अतिदेय हो चुके हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होना गर्व की बात : सीएम योगी

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित किए जाने को गर्व का पल बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय उस उत्सव की वैश्विक पहचान है, जो अंधकार पर प्रकाश की विजय और नए आरंभ के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह उपलब्धि भारत की सांस्कृतिक शक्ति व परंपरा की महत्ता को विश्व पटल पर अधिक मजबूती प्रदान करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म श्एक्सश् के माध्यम से विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से इस उपलब्धि के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उत्तर प्रदेश के लिए इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अयोध्या प्रभु श्रीराम की पावन भूमि है। यहीं पर दीपावली की पहली ऐतिहासिक उत्सव परंपरा की शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा कि अयोध्या केवल सांस्कृतिक आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि भारतीय परंपराओं की आत्मा है। ऐसे में इस पर्व की वैश्विक मान्यता अयोध्या के आध्यात्मिक महत्व को और भी प्रखर बनाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय सम्मान भारत की बढ़ती सांस्कृतिक प्रतिष्ठा का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विश्व स्तर पर अपनी सांस्कृतिक उपस्थिति को व्यापक रूप से स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि भारत की परंपराओं और उत्सवों को विश्व समुदाय द्वारा अपनाया जाना सकारात्मक संकेत है। सीएम योगी ने आशा व्यक्त की कि अयोध्या का शाश्वत प्रकाश मानवता को सत्य और सद्भाव के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला मणिपुर दौरा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार से मणिपुर का दो दिवसीय दौरा शुरू करेंगी। इस दौरान वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ महिलाओं के संघर्ष को याद करने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगी और संभवत मणिपुर के प्रसिद्ध श्री गोविंदाजी मंदिर में पूजा–अर्चना भी करेंगी। यह राष्ट्रपति मुर्मू का पहला दौरा है, जब से वे भारत की राष्ट्रपति बनी हैं। उनका दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सितंबर 2025 में मणिपुर दौरे के तीन महीने बाद हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबसे पहले दोपहर में इंफाल पोलो ग्राउंड में युवा मामले और खेल विभाग द्वारा आयोजित पोलो कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे संभवतः श्री गोविंदाजी मंदिर में पूजा करेंगी, जो मणिपुर में वैष्णव धर्म का प्रमुख केंद्र है। शाम को वे सिटी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित नागरिक स्वागत समारोह में भाग लेंगी और रात को लोक भवन में ठहरेंगी। वहीं बात अगर दूसरे दिन की करें तो शुक्रवार को वे नूपी लान समारोह में शामिल होंगी। यह समारोह हर साल महिलाओं द्वारा 1904 और 1939 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ किए गए आंदोलनों की याद में मनाया जाता है। इसके अलावा वे नागा बहुल सेनापति जिले में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हो सकती हैं। राष्ट्रपति दौरे के चलते मणिपुर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कारण है कि कई आंतरिक सशस्त्र संगठन और प्रतिबंधित समूहों ने राष्ट्रपति दौरे के विरोध में बंद बुलाया है। इस कारण इंफाल घाटी में बाजार, स्कूल–कॉलेज बंद हैं और सड़कें सुनसान हैं। राष्ट्रपति के दौरे वाले स्थानों पर कई पोस्टर और अस्थायी प्रवेश द्वार भी लगाए गए हैं। मणिपुर के मीतेई संगठन अरंबाई टेंगोल (एटी) ने राष्ट्रपति से अंतरविभागीय विस्थापितों की समस्या उठाने और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करने की अपील की है।

लोगों को संघ के बारे में समझाने के लिए व्यापक जन सहभागिता की आवश्यकता : मोहन भागवत

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि जनता के साथ गहरी संवाद प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि संघ की अब तक की यात्रा "तथ्यों की तुलना में धारणाओं" के माध्यम से फैली है। संघ प्रमुख ने कहा, "इस संदर्भ में, देशभर में नए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें संघ के स्वयंसेवक लोगों से बातचीत करेंगे और इसके बारे में "सटीक और तथ्यात्मक" रूप से जानकारी साझा करेंगे।" भागवत ने यहां आयोजित कार्यक्रम "संघ की 100 वर्ष की यात्रा – नए क्षितिज" में यह बात कही। उन्होंने कहा, "संगठन ने 100 वर्षों का कार्य पूरा कर लिया है और पिछले 10–15 वर्षों से संघ नियमित चर्चा का विषय भी बन गया है। जब चर्चा होती है, तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि शुभचिंतक भी और विरोधी भी धारणाओं के आधार पर बात करते हैं, न कि तथ्यों के आधार पर। देखा जाये तो मोदी के उत्तराधिकारी के बारे में मोहन भागवत का बयान राजनीतिक रूप से संयमित और रणनीतिक है। एक ओर उन्होंने उत्तराधिकार के प्रश्न से खुद को दूर रखकर यह संदेश दिया है कि भाजपा नेतृत्व अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है। दूसरी ओर उन्होंने सामाजिक एकता और 'विश्वगुरु' की अवधारणा को केंद्र में रखकर संघ के दीर्घकालिक एजेंडे को मजबूती से पेश किया। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि उत्तराधिकार बहस यहीं समाप्त हो गई। दरअसल, राजनीति में संकेत कई बार वास्तविकता से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं और भागवत का यह बयान भी उसी श्रेणी में आता है। परंतु इतना निश्चित है कि संघ खुद को औपचारिक रूप से इस बहस से दूर दिखाकर भाजपा के भीतर किसी भी संभावित शक्ति संतुलन को खुला छोड़ देना चाहता है।

अमित शाह और मोहन भगवत अंडमान-निकोबार दौरा करेंगे

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भगवत गुरुवार से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर जा सकते हैं, जहां वे विनायक दामोदर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस महत्वपूर्ण दौरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कुछ क्षेत्रों में यातायात प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही भगवत श्री विजयपुरम के डॉलीगंज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ताओं से संक्षिप्त बातचीत कर सकते हैं। मोहन भागवत का सरसंघचालक के रूप में यह पहला दौरा होगा। लगभग दो दशक पहले भगवत ने सरकार्यवाह (महासचिव) के रूप में द्वीप समूह का दौरा किया था, जबकि शाह का यह दूसरा दौरा होगा। उन्होंने जनवरी 2023 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के उपलक्ष्य में द्वीप समूह का दौरा किया था। अधिकारी ने बताया कि 12 दिसंबर को दोनों सुबह करीब 9:30 बजे दक्षिण अंडमान के बेओदनाबाद में सावरकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और शाम को डॉ. बी. आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान (डीबी आरएआईटी) में आयोजित एक कार्यक्रम में सावरकर पर एक गीत का विमोचन करेंगे। 13 दिसंबर को भगवत शाम को श्री विजयपुरम स्थित आईटीएफ ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित कर सकते हैं और 14 दिसंबर को द्वीपसमूह से रवाना हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री 12 दिसंबर की रात या अगली सुबह द्वीपों से रवाना हो सकते हैं। यह पूरा कार्यक्रम महाराष्ट्र स्थित एक व्यापारिक समूह द्वारा सावरकर की प्रतिष्ठित कविता सागर प्राण तलमाला (हे सागर, मेरी आत्मा तड़प रही है, मुझे मेरी मातृभूमि ले चलो) की रचना की 116वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने यह कविता 1909 में लिखी थी। सावरकर को अंग्रेजों द्वारा 1911 में पोर्ट ब्लेयर (जिसे अब श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाता है) की सेलुलर जेल में कैद कर दिया गया था।

राज्यसभा में उठा निजी अस्पतालों के मनमाने बिल और घटिया दवाओं का मुद्दा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राज्यसभा में सदस्यों ने निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से मनमाने बिल वसूले जाने तथा घटिया दवाओं का मुद्दा गुरुवार को प्रमुखता से उठाया। भारतीय जनता पार्टी के डा के लक्ष्मण ने सभापति की अनुमति से उठाये जाने वाले मामलों के तहत निजी अस्पतालों में मरीजों से भारी भरकम राशि वसूले जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अस्पताल मरीजों के उपचार के दौरान बेवजह की जांच और टेस्ट कराते हैं। स्वस्थ होने के बावजूद मरीजों को ज्यादा समय तक भर्ती रखते हैं और अनाप–शनाप बिल वसूले जाते हैं।उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए कहा कि अभी हाल ही में उपभोक्ता फोरम ने इस तरह के एक मामले में एक निजी अस्पताल को मरीज को तीन लाख रूपये का भुगतान करने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा मरीजों से परामर्श शुल्क के नाम पर 1500 से तीन हजार तक शुल्क लिए जाने की भी बात कही। डा लक्ष्मण ने अस्पतालों के बिलों को पारदर्शी बनाये जाने तथा मरीजों का संरक्षण किये जाने की मांग की। कांग्रेस की जेबी माथेर हीशम ने केरल में घटिया और कम गुणवत्ता वाली दवाओं की भरमार का मुद्दा उठाया। केरल में सत्तारूढ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की टोकाटोकी के बीच उन्होंने कहा कि राज्यभर में इन दवाओं की धड़ल्ले से बिक्री की जा रही है जिससे मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष ने प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं को उठाया। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से बंगला भाषी श्रमिकों को दिल्ली और एनसीआर में अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें बंगलादेशी करार दिया जा रहा है और जबरदस्ती बंगलादेश भेजा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य है।

खिलाड़ियों को महाराजा यादवेंद्र इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में किया जाएगा सम्मानित : भगवंत मान

चंडीगढ़, (एजेंसी)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व कप 2025 का खिताब जीता था। भारतीय महिला टीम का यह पहला आईसीसी खिताब है। विश्व चौंपियन टीम में शामिल पंजाब के खिलाड़ियों को न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सम्मानित किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने आधिकारिक श्एक्सश् अकाउंट के माध्यम से इसकी जानकारी दी।भगवंत मान ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, ष्गुरुवार शाम 5:30 बजे क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला टीम की पंजाबी खिलाड़ियों हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अमनजोत कौर, हरलीन कौर देओल और उनके कोचिंग स्टाफ को पंजाब सरकार मुल्लांपुर के नए स्टेडियम में सम्मानित करेगी। स्टेडियम में युवराज सिंह और हरमनप्रीत के नाम पर एक स्टैंड का भी उद्घाटन किया जाएगा। चक दे इंडिया।महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा टी20 मैच भी खेला जाना है। मैच शुरू होने से पहले विश्व विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। पंजाब सरकार ने हरमनप्रीत कौर, अमनजोत कौर, हरलीन कौर को विश्व कप जीत के बाद 1.5 करोड़ की राशि सम्मानस्वरूप देने की घोषणा भी की थी। हरमनप्रीत कौर भारत की पहली महिला कप्तान हैं जिनके नाम भारत को विश्व कप जिताने का रिकॉर्ड जुड़ गया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि की वजह से ही पंजाब सरकार ने उनके नाम महाराजा यादवेंद्र इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर में एक स्टैंड करने का फैसला किया है।

नक्सलवाद पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र, हमने इस समस्या को जड़ से मिटा दिया : मोहन यादव

नई दिल्ली, (एजेंसी)। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि कांग्रेस ने नक्सलवाद को लेकर दोहरा रवैया अपनाया जबकि भारतीय जनता पार्टी पार्टी (भाजपा) की सरकार ने इसे जड़ से मिटा दिया है। यादव ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा, ''राज्य में कांग्रेस के (पूर्ववर्ती) शासनकाल में नक्सलवाद बहुत बड़ी समस्या थी। हमने इस समस्या को जड़ से मिटा दिया है। सूबे के मंडला, बालाघाट और डिंडोरी जिले नक्सलियों से तकरीबन मुक्त हो चुके हैं।'' उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस के शासनकाल के दौरान नक्सलियों ने एक मंत्री की हत्या कर दी थी। यादव ने दिग्विजय सिंह का नाम लिए बगैर कहा,''नक्सलवाद की समस्या की मूल जड़ सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे जो आज भी (नक्सली कमांडर) माड़वी हिड़मा के मारे जाने पर दुख व्यक्त करते हैं। यह रवैया कांग्रेस का दोहरा चरित्र बताता है।'' उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल आरोप लगाने की राजनीति में यकीन रखती है और इस पार्टी की पिछली सरकारों ने नक्सलवाद जैसी समस्याओं को जिंदा रखा। यादव ने 13 दिसंबर 2023 को मध्यप्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। उन्होंने अपनी सरकार की पिछले दो साल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि इस अवधि में महिलाओं, किसानों, युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों के हितों में कई कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में चिकित्सा महाविद्यालयों की तादाद दोगुनी हो गई है और औद्योगिक विकास दर राष्ट्रीय औसत को पार कर गई है।

राहुल गांधी ने फिर गृहमंत्री अमित शाह पर साधा निशाना

नई दिल्ली, (एजेंसी)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर अपना हमला जारी रखा, जिन्होंने लोकसभा में चुनाव सुधार पर बहस के दौरान कांग्रेस पार्टी की जमकर आलोचना की थी। राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री ने उनके किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी कल बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया, उनके हाथ कांप रहे थे... वे बहुत मानसिक दबाव में हैं। यह सबने कल देखा। मैंने उनसे जो भी पूछा, उन्होंने उसका सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। मैंने उन्हें सीधे तौर पर चुनौती दी है कि वे मैदान में आएं और संसद में मेरी सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें। मुझे कोई जवाब नहीं मिला। एक अन्य कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा कि जो पारदर्शिता होनी चाहिए थी, वह नहीं दिखी। हरियाणा में जो हुआ, उन्होंने उसके असली सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि कांग्रेस पर आरोप लगाए। आज जो हो रहा है, उसका कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी ओर, भाजपा ने कांग्रेस और लोकसभा के विपक्ष के नेता पर शहिट एंड रनश की रणनीति अपनाने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद पर हमला करते हुए कहा, ष्राहुल गांधी शहिट एंड रनश का फॉर्मूला अपनाते हैं... जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बोलते हैं, तो वे बाहर चले जाते हैं, यही उनकी लोकतंत्र है। उनमें सच सुनने की हिम्मत नहीं है। कल केंद्रीय गृह मंत्री की बात सुनकर उन्हें बुरा लगा। मेरा मानना छ्है कि राहुल गांधी को यह आदत छोड़नी होगी... गृह मंत्री के भाषण से पूरा नेहरू परिवार बिखर गया। बुधवार को लोकसभा में तनाव तब बढ़ गया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच वोट चोरी के आरोपों पर तीखी बहस हुई। गांधी ने बार–बार शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए मुद्दों पर बहस करने की चुनौती दी, जिसमें मतदाता सूची में अनियमितताओं के दावे भी शामिल थे। शाह ने दृढ़ता से जवाब देते हुए कहा, ष्संसद उनकी मर्जी से नहीं चलेगी,ष और जोर देकर कहा कि वे सभी सवालों का जवाब अपने क्रम में देंगे। शाह ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) का भी बचाव किया और इसे मतदाता सूचियों को शुद्ध करने की एक आवश्यक प्रक्रिया बताया।

संपादकीय

एसआईआर बड़ा मुद्दा

एसआईआर संसद के शीतकालीन सत्र में विवाद का बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। उचित होगा कि सरकार पुराने संसदीय नियमों का हवाला देकर मौजूदा हाल पर बहस को ना रोके। सदन में सबको अपनी बात कहने दी जाए। किसी प्रक्रिया के जारी रहने के दौरान उसके नियम बदलते रहें, तो उसे इसकी मिसाल ही समझा जाएगा कि संबंधित संस्था ने काम शुरू करने के पहले पर्याप्त तैयारी नहीं की। उस हाल में वह प्रक्रिया विवादों से घिरती जाए, यह लाजिमी है। इसकी पूरी जिम्मेदारी संचालक संस्था पर ही आएगी। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर यह बात पूरी तरह लागू होती है। इसको लेकर पहले ही चेताया गया था कि इस कार्य को लेकर निर्वाचन आयोग जल्दबाजी दिखा रहा है। साथ ही इसकी विश्वसनीयता को लेकर भी वह गंभीर नहीं है। बिहार में पुनरीक्षण के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर कई बार उसे नियम बदलने पड़े, लेकिन उससे भी आयोग ने सबक नहीं लिया। पुराने अंदाज में 12 राज्यों में सीमित समय के भीतर यह कार्य संपन्न कराने की जिद उसने दिखाई। नतीजा है कि यह प्रक्रिया अब पहले से भी अधिक विवादित हो चुकी है। बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की आत्महत्या, काम के दबाव से मौत, और उनके तनावग्रस्त होने की खबरों ने आक्रोश एवं संशय का जो माहौल बनाया, उसी का नतीजा है कि बीच कार्य के दौरान आयोग को बीएलओ और सुपरवाइजरों के मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि में वृद्धि करनी पड़ी। और अब एसआईआर फॉर्म इकट्ठा करने, इन्हें डिजटल रूप देने, तथा अस्थायी मतदाता सूची को जारी करने की समयसीमा बढ़ानी पड़ी है। साथ ही अब जाकर आयोग ने एलान किया है कि जो नए नाम शामिल होंगे और जिन्हें हटाया जाएगा, सूची जारी होने के पहले उनकी लिस्ट राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों को दी जाएगी। सवाल है कि यह नियम आरंभ में ही घोषित क्यों नहीं होना चाहिए था दरअसल, वे तमाम नियम आरंभ से लागू क्यों नहीं होने चाहिए थे, जो न्यायिक आदेश के कारण इसका हिस्सा बने एसआईआर का प्रश्न संसद के शीतकालीन सत्र में विवाद का एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। सरकार के लिए उचित होगा कि पुराने संसदीय नियमों का हवाला देकर मौजूदा हाल पर बहस को वह ना रोके। बल्कि सदन में सबको अपनी बात कहने दी जाए। चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए यह अनिवार्य है।

अमेरिका ने पाक पर लगाया करोड़ों डॉलर का दाँव

नीरज

अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान के सबसे अस्थिर और विद्रोह–ग्रस्त प्रांत बलूचिस्तान में स्थित रिकोडिक सोना खदान के लिए 1.25 अरब डॉलर के यूएस बैंक वित्तपोषण को मंजूरी दे दी है। यह

वही परियोजना है जिसे वर्षों से सुरक्षा संकट, राजनीतिक विवाद और बलूच विद्रोहियों की हिंसा ने कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। इस निवेश के साथ निकट भविष्य में 2 अरब डॉलर तक की अमेरिकी मशीनरी और सेवाएँ पाकिस्तान भेजी जाएँगी। अमेरिकी चार्ज द'अफेयर्स नटाली बेकर ने कहा है कि यह परियोजना अमेरिका के लिए 6,000 और बलूचिस्तान में 7,500 नौकरियाँ उत्पन्न करेगी। उन्होंने रिकोडिक को दोनों देशों के लिए लाभकारी आदर्श मॉडल बताया है। हम आपको बता दें कि रिकोडिक दुनिया के सबसे बड़े अविकसित तांबादृ सोना भंडारों में से एक है। माना जाता है कि यहां 15 मिलियन टन तांबा और 26 मिलियन औंस सोना है। कनाडा की दिग्गज कंपनी बैरिक गोल्ड पहले ही 2028 तक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य तय कर चुकी है। इस परियोजना का 50: मालिकाना बैरिक के पास है, जबकि पाकिस्तानी संघीय व बलूचिस्तान सरकार के पास 25–25% हिस्सेदारी है। रिपोर्टों के अनुसार इस परियोजना से 37 वर्षों में 70 अरब डॉलर से अधिक मुक्त नकदी प्रवाह उत्पन्न होने की संभावना है। हालाँकि, सुरक्षा खतरे सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। बलूच विद्रोही गुट लगातार सेना, खानन परियोजनाओं और विदेशी निवेश पर हमले करते रहे हैं। हाल ही में बलूच नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी कि कोई भी विदेशी निवेशक बलूचिस्तान के कब्जे को वैधता देने की गलती नहीं करे। बलूच नेशनल मूवमेंट के अध्यक्ष नसीम बलूच ने इसे बलूच जनता की संपत्ति पर पाकिस्तानी कब्जे को बढ़ावा देने वाला कदम बताया। इसी बीच विश्व बैंक की ष्ठ, एशियन डेवलपमेंट बैंक और अन्य वैश्विक उधारदाता 2.6 अरब डॉलर से अधिक का वित्त पैकेज जोड़ रहे हैं। साथ ही सऊदी अरब की मनारा मिनरल्स भी 10–20% हिस्सेदारी खरीदने पर बातचीत कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि क्या पाकिस्तान इतने लंबे समय तक सुरक्षा, बुनियादी ढाँचे और राजनीतिक स्थिरता की गारंटी दे पाएगा? देखा जाये तो अमेरिकी निवेश ऐसे समय में आया है जब वाशिंगटन चीन–प्रभुत्व वाली खनिज आपूर्ति शृंखलाओं से बाहर निकलने के लिए नए स्रोत तलाश रहा है। फिर भी, रिकोडिक पर यह दाँव एक हाई–रिस्क जुआ माना जा रहा है। यह भी देखने में आ रहा है कि रिकोडिक में अमेरिकी निवेश सिर्फ आर्थिक सौदा नहीं बल्कि यह भू–राजनीतिक शतरंज की बिसात पर फेंकी गई भारी–भरकम चाल है। पाकिस्तान इसे बड़ी जीत बताकर छाती ठोक रहा है पर असलियत यह है कि अमेरिका ने यह पैसा दक्षिण एशिया के सबसे अस्थिर इलाके में आग से खेलने के अंदाज में डाला है। सवाल यह नहीं कि अमेरिका क्यों आया? सवाल यह है कि वह इतना देर से और इतनी जगह पर क्यों आया? हम आपको बता दें कि यह निवेश उस समय हो रहा है जब बलूचिस्तान में विद्रोह चरम पर है। बलूच नेता साफ चेतावनियाँ दे रहे हैं कि यह निवेश उनके लिए शोषण का नया अध्याय है। बलूच नेता कह रहे हैं कि प्रांत में दशकों से मौजूद असंतोष और सैन्य दमन को देखते हुए कोई भी समझदार निवेशक पहले सौ बार सोचे। लेकिन अमेरिका ने शायद जानबूझकर जोखिम को स्वीकार कर लिया है। ऐसा लगता है कि यह सौदा पाकिस्तानी नहीं, बल्कि अमेरिकी एजेंडे का हिस्सा है। दरअसल, अमेरिका का असली मकसद है चीन को पछाड़ना। आज की सच्चाई यह है कि दुनिया में तांबा, सोना और अन्य क्रिटिकल मिनरल्स नई सदी का तेल बन चुके हैं। चीन खासकर अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में इस क्षेत्र में भारी पकड़ बना चुका है। अमेरिका बड़ी तेजी के साथ नए स्रोत ढूँढ़ रहा है और पाकिस्तान का रिकोडिक, जो तिब्बतीदृईरानी खनिज बेल्ट का हिस्सा है वह अमेरिकी रणनीति में एक खूबसूरत चेकमेट जैसा दिखता है। इसके साथ ही बलूचिस्तान का भौगोलिक महत्व इस कदम को और तीखा बनाता है। ईरान की सरहद पास है, अफगानिस्तान की अनिश्चितता बगल में है, चीनदृ पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ठीक सिर के ऊपर है। ऐसे में अमेरिका एक ही प्रहार में चीन को संकेत देता है कि हम अभी भी आपके बगल में मौजूद हैं और आपके बंदरगाह (ग्वादर) के पीछे की जमीन पर निवेश करने की ताकत रखते हैं। वहीं पाकिस्तान इस निवेश को आर्थिक राहत समझ रहा है, लेकिन असल में वह एक रणनीतिक जाल में फँसता दिख रहा है। देश की सुरक्षा एजेंसियों का इतिहास बताता है कि वह बलूचिस्तान को सेना–प्रभुत्व वाला इलाका मानती हैं। पर विदेशी निवेश वहीं चलता है जहाँ जनता को न्यूनतम सहमति या सुरक्षा मिले। यह दोनों ही पाकिस्तान के पास नहीं हैं। रिकोडिक के लिए न रेल लाइन है, न स्थायी सड़कें, न विश्वसनीय सुरक्षा तंत्र। ऊपर से बलूचिस्तान में हर विदेशी निवेश, चाहे चीनी हो, सऊदी हो या अब अमेरिकी, यह विद्रोही गुटों का प्राथमिक निशाना बन जाता है। सवाल उठता है कि कनाडा की बैरिक गोल्ड इतने वर्षों में हिल–डुल भर नहीं सकी तो अमेरिका किस आत्मविश्वास से यहां आ रहा है? अमेरिका के इस क्षेत्र में आने से यह भी आशंका है कि चीनदृ अमेरिका प्रतिस्पर्धा नई तीव्रता पर पहुँचेगी। दरअसल, अमेरिका रिकोडिक को चीन की आपूर्ति शृंखला का प्रभुत्व तोड़ने के लिए इस्तेमाल करेगा। ऐसे में पाकिस्तान दोनों महाशक्तियों के बीच रस्साकशी में फँस जाएगा। इस परियोजना से ईरान भी असहज होगा क्योंकि अमेरिका समर्थित विशाल रणनीतिक परियोजना उसकी सीमा के ठीक पास उभरना तेहरान को बिल्कुल रास नहीं आएगा। साथ ही अमेरिकी परियोजना से अफगानिस्तान का प्रभाव भी बढ़ेगा क्योंकि इसकी सुरक्षा और आपूर्ति रूट तालिबान द्वारा नियंत्रित इलाकों के बेहद करीब हैं। तालिबान इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। साथ ही इस परियोजना से बलूच विद्रोह को नई ऊर्जा मिलेगी। विदेशी निवेश उनके लिए हमेशा दमन के नए प्रतीक के रूप में देखा गया है। परिणामस्वरूप सुरक्षा स्थिति और बिगड़ सकती है। बहरहाल, यह निवेश पाकिस्तान के लिए आर्थिक संजीवनी नहीं बल्कि शक्ति के वैश्विक खेल में एक गैंबलिंग चिप है। अमेरिका को चाहिए क्रिटिकल मिनरल्स, पाकिस्तान को चाहिए डॉलर, लेकिन बलूचिस्तान को चाहिए न्याय, अधिकार और सुरक्षा जो किसी भी सौदे में शामिल नहीं हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि रिकोडिक आने वाले वर्षों में दक्षिण एशिया की नई भू–रणनीतिक लड़ाई का केंद्र बन सकता है। साथ ही अगर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की राजनीतिक समस्या को सैन्य तरीके से संभालने की भूल जारी रखी, तो अमेरिकी निवेश भी उसी तरह डूबेगा जैसे पहले के तमाम विदेशी प्रोजेक्ट डूब चुके हैं। यह सही है कि अमेरिका ने एक बड़ा दाँव लगाया है लेकिन यह भी सच्चाई है कि यह दाँव जितना चमकदार दिखता है, उतना ही बारूद के ढेर पर रखा हुआ है।

कांग्रेस का सुख, मोदी का दुख

सर्वमित्रा

किसी देश के लिए दो सदियों तक गुलाम रहना और फिर भी अपनी आत्मा को बचाए रखना आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत ने हर तरह से भारत को तोड़ने की कोशिश की। हमारे रंग से लेकर भाषा, पहनावे, रीति–रिवाज, सामाजिक–सांस्कृतिक–धार्मिक वैविध्य सबका मखौल उड़ाया। फिर भी अंग्रेजों के सामने भारतीय डटे रहे। 1857 से लेकर 1947 तक एक लंबा संघर्ष आजाद होने के लिए चलता रहा। नरेन्द्र मोदी के अंधसमर्थकों ने उन्हें दैवीय पुरुष बना दिया है। मोदी खुद को ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा से संपन्न अवतरित बता चुके हैं, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि उन्हें लगता नहीं कि वे अपनी मां की कोख से जैविक तौर पर जन्मे हैं। देश का मीडिया दिन–रात मोदी–मोदी के नाम की माला जपता है और विदेशों में जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहां भी उनके नाम की दीवानगी दिखाई जाती है। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जब साक्षात मोदी को देखकर लोग अपनी खुशकिस्मती पर रो पड़े। इतना यश, सम्मान, सत्ता, संपत्ति, सुविधाएं सब मिलने के बावजूद न जाने कौन सी हीन ग्रंथि है जो नरेन्द्र मोदी को असली सुख से वंचित रख रही है। वो सुख जो देश के विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को हासिल है कि आज भले वे कम वोट मिलने से हार रहे हैं, लेकिन इस देश को बनाने में उनका जो योगदान रहा है, उसे सब याद करते हैं। देश उस पेड़ के फल तोड़ रहा है, उस पेड़ की छाया में चौन पा रहा है, जो आजादी के वक्त कांग्रेस और उसके साथियों ने लगाया था। संविधान नाम के इस पेड़ के बीज दो सौ साल की गुलामी से छुटकारा पाकर लगाए गए थे।किसी देश के लिए दो सदियों तक गुलाम रहना और फिर भी अपनी आत्मा को बचाए रखना आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत ने हर तरह से भारत को तोड़ने की कोशिश की। हमारे रंग से लेकर भाषा, पहनावे, रीति–रिवाज, सामाजिक–सांस्कृतिक–धार्मिक वैविध्य सबका मखौल उड़ाया। फिर भी अंग्रेजों के सामने भारतीय डटे रहे। 1857 से लेकर 1947 तक एक लंबा संघर्ष आजाद होने के लिए चलता रहा, जिसमें लाखों लोगों ने कुर्बानियां दीं। मगर इन लाखों लोगों में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने एक भी पुरखे का नाम नहीं बता पाता है। नरेन्द्र मोदी नहीं बता सकते कि वे जिस विचारधारा की राजनीति करते हैं, उसके प्रणेताओं का आजादी की लड़ाई में क्या योगदान है। यही वह हीन ग्रंथि है, जो उन्हें सत्ता के शीर्ष पर होने के बावजूद बेचौन रखे हुई है। और ये बेचौनी तब और बढ़ जाती है, जब याद दिलाया जाता है कि नेहरू खानदान ने देश को आजाद कराने के लिए कितना योगदान और कुर्बानी दी। और जब आजाद लेकिन बेहद कमजोर हो चुके देश को बतौर प्रधानमंत्री नेहरूजी ने संभाला तो कितनी जल्दी उसे विकासशील देशों की कतार में खड़ा कर दिया।पिछले 11 सालों से नरेन्द्र मोदी नेहरू जी को कमतर दिखाने की कोशिश में लगे हैं और उनसे पहले ये काम संघ के लोग करते चले आ रहे हैं। लेकिन किसी भी तरह उन्हें सफलता नहीं मिल रही। ऊपर से लोग सवाल और कर देते हैं कि बताओ जब अंग्रेज स्वाधीनता सेनानियों पर अत्याचार कर रहे थे, तो आपके पुरखे उनका साथ क्यों दे रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों की मदद क्यों कर रहे थे। जब देश के लिए जेल जाते वक्त लोग इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम् के नारे लगाते थे, तब आपके पुरखे कहां छिप कर बैठे थे। इन सवालों का कोई जवाब जब नरेन्द्र मोदी नहीं तलाश पाए तो उन्होंने वंदे मातरम् के डेढ़ सौ साल पूरे होने पर संसद में चर्चा कराने का दांव चला। मोदी को लगा होगा कि कम से कम इस तरह वे इतिहास में अपना नाम दर्ज करा पाएंगे कि एक प्रधानमंत्री ऐसा भी हुआ जिसने सारे जरूरी मुद्दों को छोड़कर राष्ट्रगीत पर चर्चा कराकर अपनी देशभक्ति दिखाई। लेकिन हाय रे किस्मत, नरेन्द्र मोदी यहां भी मात खा गए।उन्हें क्या पता था कि जिन जरूरी मुद्दों पर चर्चा से बचना था, वो वंदेमातरम् पर चर्चा के साथ ही उठ जाएंगे। वंदे मातरम् पर 10 घंटों की चर्चा में मोदी के भाषण समेत भाजपा के तमाम नेताओं के भाषणों में नेहरू से कमतर होने की कुंठा नजर आई। इनके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में कहा भी कि नेहरूजी का कद ऊंचा है और ऊंचा ही रहेगा। और आप नीचे हैं, नीचे ही रहेंगे। अब भाजपा के लोग इस बात का भला–बुरा मानते रहें, लेकिन सच्चाई तो वो झुठला नहीं सकते। रहा सवाल वंदे मातरम् का, तो उस पर प्रियंका गांधी ने बखूबी जवाब दिया है कि मोदीजी ने ये तो कहा कि एक अधिवेशन में रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने वंदेमातरम् का गान किया था, लेकिन वे ये नहीं कह पाए कि वो अधिवेशन कांग्रेस का था। प्रियंका ने पूछा कि कांग्रेस अधिवेशनों में तो हमेशा वंदे मातरम् गाया जाता है, संघ या भाजपा के कार्यक्रमों में ऐसा क्यों नहीं होता।इसी तरह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम तो शुरु से वंदे मातरम् बोल रहे हैं और आगे भी कहेंगे, लेकिन आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया। विपक्ष की तरफ से तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोईत्रा और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी जबरदस्त भाषण दिए। महुआ मोईत्रा ने वंदे मातरम् के अंतरों की व्याख्या करके मोदी सरकार का सच से साक्षात्कार करवा दिया। उन्होंने कहा कि जिस श्मांश को हम प्रणाम करते हैं, सत्ता ने उसे नारे में बदल दिया है। सुजलाम, सुफलाम का मतलब समझाते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा कि जिस श्धराश को शस्य–श्यामला कहा, उसका किसान कर्ज और सूखे में टूट रहा है। जिस श्जलश को जीवन माना, उसी जल पर ठेके और कंपनियां कब्जा कर रही हैं। मलयज शीतलाम, यानी ठंडी, सुखद हवा आज नहीं बची है, दिल्ली प्रदूषण में हांफ रही है। सुखदाम, वरदाम यानी सुख और वरदान देने वाली मां के बच्चे आज दम तोड़ रहे हैं। महुआ मोईत्रा ने यहां कई बीएलओ की मौत का जिक्र किया, जो एसआईआर के काम में लगे थे, लेकिन उनकी अकाल मौत हुई और सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता सिर्फ नारा बचा रही है, भूमि की पीड़ा नहीं। वंदे मातरम् सिर्फ गीत नहीं, चेतना है। और चेतना को घायल कर गीत का जाप करने से देशभक्ति नहीं बचती।वहीं संजय सिंह ने भगत सिंह जैसे अमर शहीदों का जिक्र कर भाजपा से पूछा कि संघ के चार लोगों के नाम बता दो जो वंदे मातरम् कहते हुए जेल चले गए या फांसी के तख्ते को चूम लिया। कुल मिलाकर वंदे मातरम् पर

चर्चा करवाकर मोदी जो सियासी लाभ हासिल करना चाहते थे, वह और बड़ा नुकसान करवा गया। बस अच्छी बात यह हुई कि संसद के जरिए देश एक बार फिर आजादी के इतिहास की गलियों में घूम आया। इस इतिहास में ये बात भी दर्ज है कि कांग्रेस ने जिस सांप्रदायिक नजरिए को दूर रखने के लिए वंदेमातरम् के केवल पहले दो अंतरों को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया, शहीदे आजम भगत सिंह के विचार भी वही थे। क्रांतिकारी व लेखक यशपाल ने सिंहावलोकन में लिखा है कि भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा में तय किया था कि धर्मनिरपेक्षता को दर्शाने के लिए अल्लाहू अकबर, सत श्री अकाल और वंदेमातरम् के नारे न लगाकर इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाएंगे। तो अब क्या मोदी भगत सिंह और उनके साथियों की देशभक्ति पर भी सवाल उठाएंगे। वैसे इतिहास को पढ़ने, जानने और समझने वाले ये बात जानते हैं कि वंदे मातरम्, जयहिंद और इंकलाब–जिंदाबाद यही तीन नारे स्वाधीनता आंदोलन में गूंजा करते थे। इनके अलावा डॉ. अल्लामा इकबाल की अमर रचना सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा भी कौमी तराना माना जाता था। आज भी स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस पर यह गाया जाता है। इसकी धुन प्रख्यात सितारवादक पंडित रविशंकर ने तैयार की थी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना जैसी पंक्ति लिखने वाले और हिंदू और मुस्लिम को एक चेहरे पर दो सुंदर आंखें कहने वाले इकबाल खुद पाकिस्तान चले गए। लेकिन इससे सारे जहां से अच्छा का महत्व कम नहीं हो जाता। वंदे मातरम् तो कांग्रेस की सभाओं गाया जाता था। वहीं नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की आजाद हिंद फौज के लिए जयहिंद नारा गढ़ा गया। नेताजी ने जब आजाद हिंद फौज का गठन किया, तो उनके अपने फौजी जवानों के अभिवादन के लिए किसी शब्द की जरूरत महसूस हुई। नेताजी के सचिव आबिद हसन सफरानी ने तब जयहिंद का नारा गढ़ा। 1946 में एक चुनावी सभा में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जनता से जयहिंद का उद्घोष करने का आह्वान किया था।

सामाजिक सुरक्षा की ओर कदम– श्रम संहिताएँ और डिजिटल ढाँचा

जी. मधुमिता दास

सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ गरीबी कम करने, मजबूती बढ़ाने और न्यायसंगत विकास को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रत्येक निवासी को, उसकी आय, रोजगार की स्थिति या जनसांख्यिकीय विशेषता की परवाह किए बिना, पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल, बेरोजगारी भत्ता या दिव्यांगता सहायता जैसे न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुँच प्रदान करता है। भारत अब सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने की दिशा में पहले से कहीं अधिक नजदीक है–एक ऐसी प्रणाली जिसे अधिकांश राष्ट्र, यहाँ तक कि सबसे विकसित देश भी, दशकों तक निरंतर निवेश और प्रयास करने के बाद ही स्थापित कर पाए। श्रम संहिताओं, विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के माध्यम से, देश के पास हर कामगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी ढांचा मौजूद है कृचाहे वह गिग ड्राइवर हो, फैक्ट्री कर्मचारी हो या निर्माण कार्य करने वाला प्रवासी मजदूर हो । सामाजिक सुरक्षा संहिता नौ प्रमुख कानूनों को एकल एकीकृत ढांचे में समेकित करती है। इससे प्रशासनिक जटिलता कम करने, लाभों को हस्तांतरित करने की योग्यता बेहतर बनाने, नियोक्ताओं के लिए अनुपालन सरल बनाने और निगरानी व प्रवर्तन मजबूत बनाने में मदद मिलती है। इसकी बदौलत विशेषकर असंगठित क्षेत्र के छोटे उद्यमों के कामगार कृ जहाँ भारत के 90त्न कामगार काम करते हैंकृनौकरशाही की अड़चनों में उलझे बगैर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह संहिता सरकार को भी यह अधिकार देती है कि वह सभी क्षेत्रों में उद्यमों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), मातृत्व लाभ और ग्रेच्युटी का कवरेज बढ़ा सके, ताकि अब तक असुरक्षित रहे कामगारों को लाभ मिल सके और छोटे उद्यमों में स्वैच्छिक पंजीकरण को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा, यह राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष ध् राज्य सामाजिक सुरक्षा कोष की व्यवस्था प्रदान करती है, जहाँ सरकार का वित्तीय योगदान, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का योगदान, नियोक्ता और कर्मचारियों का योगदान एकत्रित किया जा सकता है, जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज को सहायता प्रदान कर सकता है। लेकिन केवल कानून बनाना भर ही पर्याप्त नहीं है। जो बात वास्तव में भारत को उसके वैश्विक समकक्षों से अलग कर सकती है, वह है उसका उभरता डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तंत्रकृई–श्रम डेटाबेस और आधार प्रमाणीकरण से लेकर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्लेटफॉर्म तक। ये सभी उपकरण मिलकर भारत को पारंपरिक कल्याण मॉडल से आगे बढ़ने और एक पोर्टेबल, पारदर्शी, तकनीक–सक्षम कल्याण प्रणाली बनाने का अनूठा अवसर प्रदान करते हैं, जो दुनिया की किसी भी प्रणाली से अलग है। आधारः सार्वभौमिकरण की रीढ़ सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश सार्वभौमिकता सुनिश्चित करने के लिए हर निवासी को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं जो सीधे लाभों से जुड़ी होती है। भारत के पास आधार – के रूप में यह सुविधा पहले से मौजूद हैकृजो अत्यंत विश्वसनीय और निशुल्क प्रमाणीकरण प्रदान करता है। आधार सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की सबसे बड़े बाधारू अर्थात, विभिन्न राज्यों, क्षेत्रों और नियोक्ताओं में लाभार्थियों की पहचान और प्रमाणीकरण को हल करता है। प्रवासी कामगारों के लिए, आधार–सक्षम पोर्टेबिलिटी वह कर सकती है, जो पिछली पीढ़ी के कल्याणकारी सुधार हासिल नहीं कर पाए रू स्थान की परवाह किए बगैर लाभों तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करना। यह प्रणाली नॉर्वे और डेनमार्क जैसे देशों में डिजिटल आईडी आधारित प्रणालियों की तरह है, जहाँ नागरिक अपनी कल्याण पहचान को अलग–अलग क्षेत्रों और सेवाओं में निर्बाध रूप से अपने साथ रख सकते हैं। एकीकृत डेटाबेस पर आधारित एकीकृत संहिता जहाँ एक ओर दुनिया भर में संगठित क्षेत्र के कामगार सामान्यतरू सामाजिक सुरक्षा कवरेज के अंतर्गत आते हैं, वहीं नियोक्ता–कामगार के बीच स्थिर रोजगार संबंध नहीं होने के कारण असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कवर करना कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होता है । कई देश एकीकृत श्रम कानूनों पर भरोसा करते हैं, लेकिन बहुत कम देशों के पास भारत के ई–श्रम डेटाबेस जैसा विशाल राष्ट्रीय श्रमिक रजिस्टर मौजूद है। सामाजिक सुरक्षा संहिता में एकीकृत पंजीकरण तंत्र का प्रावधान ई–श्रम के साथ पूरी तरह मेल खाता है, जो पहले से ही 310 मिलियन से अधिक असंगठित क्षेत्र के कामगारों के जनसांख्यिकीय, कौशल और व्यवसाय संबंधी डेटा को संग्रहित करता है। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से प्रत्येक कामगार की विशिष्ट रूप से पहचान की जाती है और उन्हें एक ई–श्रम

परिवर्तन से गुजरती परंपरा– भारतीय हस्तशिल्प गढ़ रहे हैं आधुनिक डिजाइन की पहचान

ग्रामीण असम में शिल्पकारों की एक बस्ती की हाल की यात्रा के दौरान एक सामान्य से दृश्य में भारत के हस्तशिल्प तंत्र में आ रहे गहरे बदलाव की झलक दिखाई दी। अनेक शिल्पकार सूखी हुई जलकुंभी को बुन रहे थे। लेकिन ये शिल्पकार वे परंपरागत टोकरियां नहीं बना रहे थे जिन्हें उनका समुदाय सदियों से बुनता आ रहा है। इसके बजाय वे कॉरपोरेट बैठकों के लिए खूबसूरत ऑफिस फोल्डर बना रहे थे। उनके हाथ पीढ़ियों से जारी कला को आगे बढ़ाते हुए चिरपरिचित लय में चल रहे थे। लेकिन उनके उत्पाद और उद्देश्य, दोनों ही पूरी तरह से बदल चुके हैं। हम 08 से 14 दिसंबर, 2025 तक राष्ट्रीय हस्तशिल्प दिवस मना रहे हैं। ऐसे में, यह दृश्य भारत के हस्तशिल्प परिदृश्य में एक मूक क्रांति का प्रतीक है। हमारी जीवंत हस्तशिल्प परंपराओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है। उनका नई जगहों, नए बाजारों और नूतन भविष्य में विस्तार हो रहा है। मूल विशेषताओं की शुद्धता बरकरार रहने के बावजूद माध्यमों और स्वरूपों में जो विकास हो रहा है उसकी कल्पना एक दशक पहले शायद ही की जा सकती थी। जीवंत ज्ञान प्रणाली के रूप में हस्तशिल्प इस विकास को समझने के लिए यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि भारतीय हस्तशिल्प सिर्फ सुंदरता की वस्तु नहीं रहे हैं। वे सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक परंपराओं में गहराई से रची–बसी जीवंत ज्ञान प्रणालियां हैं। मधुबनी में महिलाएं परंपरागत तौर पर त्यौहारों, शादियों और जीवन संस्कारों के दौरान ताजा लेपी गई दीवारों पर चावल के पेस्ट से पेंटिंग बनाती थीं। इन चित्रों में मछली को जनन क्षमता और मोर को प्रेम का प्रतीक माना जाता था। चित्रण अपने मूल में व्यक्तिगत के बजाय सामूहिक हुआ करता था। गोंड समुदाय के लिए पेंटिंग उसके जीव संबंधी विश्वासों तथा जंगलवासी प्राकृतिक शक्तियों और रक्षा करने वाली आत्माओं से जुड़ी है। उनकी कला सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि वाचक परंपरा में जड़ों वाला अनुष्ठानिक ब्रह्मांड विज्ञान भी है। स्वरूपों को हमेशा उपयोग ने गढ़ा है। असम में जलकुंभी को सुखाने के बाद बुन कर घर में काम आने वाली टोकरियां बनाई जाती हैं। कर्नाटक में लाख के लेप वाले चन्नपटना काष्ठ खिलौने बच्चों के खेलने के काम आते हैं। उन्हें पीढ़ियों से खराद पर बनाया जाता रहा है। माध्यम, स्वरूप और आकृति को एकदूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। वे विशिष्ट अनुष्ठानिक और कार्यात्मक संदर्भों से आबद्ध हैं। परंपरा का आधुनिक अभिव्यक्ति में विस्तार आज जो हो रहा है, वह परंपरा से अलग नहीं, बल्कि उसका विस्तार है। मूलभाव, पैटर्न और तकनीकें अभी भी पहचानी जा सकती हैं, लेकिन उनके प्रयोग आश्चर्यजनक रूप से समकालीन हो गए हैं। यह बदलाव केवल एक आयामी नहीं, बल्कि बहु–आयामी है। मधुबनी की मछली, जो कभी एक बड़ी प्रजनन कथा का हिस्सा हुआ करती थी, अब तकिए, टोट बैग और फोन कवर पर दिखाई देती है, जिसे आज के समय के अनुसार इस्तेमाल के लिए नया रूप दिया गया है। गोंड के गहरे रंगों वाले जानवर और पौधे और ज्यामिति डिजाइन आज अपने पौराणिक संदर्भ से बाहर भी सराहे जाते हैं। हालांकि, सबसे बड़ा परिवर्तन माध्यम में आया है। जलकुंभी आज कॉर्पोरेट फोल्डर और डिजाइनर हैंडबैग का रूप ले रही है। मधुबनी कला मिट्टी की दीवारों से हटकर लकड़ी के फर्नीचर, वस्त्रों और चमड़े के सहायक उपकरणों पर की जाने लगी है। चन्नपटना शिल्प, जो कभी केवल खिलौनों में ही दिखता था, अब सजावटी नक्शों, झूमरों, गृह सज्जा और डिजाइनर फर्नीचर में दिखाई देता है। पारंपरिक लाख का अभी भी इस्तेमाल हो रहा है लेकिन उसका रूप पूरी तरह आधुनिक हो गया है। यह बदलाव आज के अनुकूल है, न कि उसका कमजोर पड़ना। भारतीय शिल्प पर आधारित फैशन की वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख पहचान बन गयी है, जिसमें पारंपरिक कढ़ाई को श्पेरिस हौते कॉउचर वीकश में प्रदर्शित किया गया था। नेशनल गैलरी ऑफ विक्टोरिया जैसे संग्रहालयों में अब ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड्स जैसी प्रदर्शनियाँ गोंड और मधुबनी कला और उनके आधुनिक रूपों को उनकी संस्कृति या समाज के संदर्भों के बजाय समकालीन कला के तौर पर चित्रित कर रही हैं। नेतृत्व और सरकारी हस्तक्षेप परिवर्तन को गति दे रहे हैं इस परिवर्तन को राष्ट्रीय नेतृत्व और रणनीतिक सरकारी हस्तक्षेपों से महत्वपूर्ण समर्थन मिला है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व ने इस आंदोलन को असाधारण गति दी है। उनका श्वोकल फॉर लोकलश और श्लोकल टू ग्लोबलश का बार–बार किया गया आह्वान कारीगरों के प्रति उनके गहरे लगाव को दर्शाता है। वह हमेशा नागरिकों से स्थानीय उत्पाद खरीदने का आग्रह करते हैं, जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है किरू जब हम ऐसा करते हैं, तो हम केवल सामान नहीं खरीदते हैंय हम एक परिवार के लिए आशा लाते हैं, एक कारीगर की कड़ी मेहनत का सम्मान करते हैं, और एक युवा उद्यमी के सपनों को पंख देते हैं। उन्होंने अपने नवीनतम मन की बात संबोधन में बताया कि वह विश्व के नेताओं के साथ मुलाकातों के दौरान जानबूझकर हाथ से बने भारतीय उत्पादों को ही उपहार के रूप में क्यों देते हैं। ऐसा करके वह यह सुनिश्चित करते हैं कि वह जहाँ भी जाएँ उनके साथ साथ भारत की समृद्ध शिल्प विरासत भी जाये।

शासनादेश जारी, शिक्षा विभाग तैयार करेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसे लगेगी अटेडेंस

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग एक डिजिटल प्लेटफार्म तैयार करेगा। इसके माध्यम से शिक्षकों की हाजिरी लगाई जाएगी। खास यह कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के समन्वय से इस व्यवस्था को प्रभावी किया जाएगा। क्योंकि वहां भी इसी तरह से शिक्षकों–शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की ऑनलाइन हाजिरी लग रही है। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने निर्देश दिया है कि इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया जाएगा। जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के समन्वय से एक डिजिटल प्लेटफार्म तैयार करवाएंगी। इसके माध्यम में माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति से संबंधित ऑनलाइन डिजिटल

प्रणाली बेसिक शिक्षा विभाग में लागू किए जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने में अभी थोड़ा समय और लगेगा। माना जा रहा है कि यह व्यवस्था नए साल 2026 में लागू होगी। हालांकि शिक्षक संगठन विभाग के इस निर्णय से सैद्धांतिक रूप से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि पहले विभाग शिक्षकों की वाजिफ मांग को पूरा करे, इसके बाद इस व्यवस्था को प्रभावी बनाए। ऐसा न करके विभाग उनके साथ वादाखिलाफी कर रहा है। बेसिक में भी माध्यमिक शिक्षा विभाग वाली व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। हालांकि वहां पर दोहरी व्यवस्था है। राजकीय व अशासकीय माध्यमिक माध्यमिक विद्यालयों में पहले डिजिटल अटेंडेंस के लिए बायोमीट्रिक मशीन लग गई थी। किंतु यह बहुत प्रभावी नहीं हो पाया। अभी भी प्रधानाध्यापक ही यूपीएमएसपी की साइट पर शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की उपस्थिति को एप्रूव करते हैं। वहीं रजिस्टर पर भी यह हस्ताक्षर करते व उनकी छुट्टी भी चढ़ती है। ऐसे में बेसिक में भी ऑनलाइन प्रधानाचार्य ही उपस्थिति एप्रूव करेंगे। इस व्यवस्था में शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक व शिक्षणेत्तर कर्मचारी सभी शामिल होंगे।

ट्राला से टकराई श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो, तीन की मौत

लखनऊ, (संवाददाता)। अयोध्या जिले के पूराकलंदर थाना क्षेत्र के कल्याण भदरसा के पास प्रयागराज हाईवे पर बृहस्पतिवार की भोर में लगभग पांच बजे श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो अनियंत्रित होकर ट्राला से टकरा गई। हादसे में बोलेरो सवार दो महिलाओं समेत तीन की मौत हो गई। जबकि, आठ लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मऊगंज निवासी चित्रसेन पटेल (50) परिवार के 10 लोगों के साथ रामलला का दर्शन करने अयोध्या आ रहे थे। वह लोग बोलेरो से बुधवार को निकले थे। बृहस्पतिवार की भोर में लगभग पांच बजे सभी कल्याण भदरसा के पास पहुंचे तो चालक को अचानक नींद लगी और वह अनियंत्रित होकर सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्राला में भिड़ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया और अफसरों को घायलों की हरसंभव मदद उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। वहीं, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं। हादसे में बोलेरो सवार चित्रसेन की बेटी अंकिता पटेल (25), महेंद्र मणि पटेल की पत्नी मीराबाई (25) व चालक राम यश मिश्रा (50) की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि, चित्रसेन उनकी पत्नी चंद्रकला (45), बेटा तनुज पटेल (20) व दीपक कुमार पटेल (35), सरोज मणि पटेल की पत्नी कुसुम (35) और बेटा आशीष पटेल (23), हरिकेश का पांच साल का बेटा शिवांश पटेल व पत्नी शशि पटेल (30) गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर आई पूराकलंदर पुलिस ने घायलों को तीन एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रभारी निरीक्षक मनोज शर्मा ने बताया कि शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। घायलों का इलाज चल रहा है।

संक्षिप्त खबरें

सामूहिक विवाह समारोह में जा रहा था दूल्हाय ऐसे गई अंकित की जान

लखनऊ, (संवाददाता)। सीतापुर जिले के इमलिया सुल्तानपुर के फरखपुर धन्नाग मार्ग पर विशुनपुर के निकट एक ऑटो अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धुंध के कारण संभवतः अज्ञात वाहन के चालक को ऑटो न दिखाई दिया हो। इस वजह से हादसा हुआ। हादसे में ऑटो सवार टीकर बहादुरपुर के अंकित कुमार (19) अपने पिता शिवकुमार (45) व माता शिवपति (42) गांव के ही ऑटो चालक अंकित सिंह (35) के साथ परसेंडी में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में माता पिता के साथ जा रहे थे। इसी दौरान हादसा हुआ। ग्रामीणों के अनुसार अंकित का आज विवाह होना था। इससे पूर्व हादसा हो गया। सभी घायलों को सीएचसी इमलिया लाया गया। वहां अंकित कुमार को चिकित्सकों ने इलाज के लिए सीतापुर जिला अस्पताल भेजा। रास्ते में ही अंकित ने दम तोड़ दिया। इंस्पेक्टर श्यामू कनौजिया ने बताया कि घायलों का उपचार जारी है। विधिक कार्रवाई की जा रही है।

परिक्रमा मार्ग पर सड़क धंसी, कुछ ही महीने पहले हुआ था निर्माण

लखनऊ, (संवाददाता)। परिक्रमा मार्ग पर सीवर निर्माण में लापरवाही का बड़ा असर दिखाई दिया है। निर्माण कार्य के दौरान गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की वजह से सड़क पूरी तरह बैठ गई जिससे आवागमन बाधित हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार परिक्रमा मार्ग का निर्माण हुए कुछ ही माह हुए थे, लेकिन सीवर लाइन डालते समय हुई तकनीकी और संरचनात्मक लापरवाही के चलते सड़क अचानक धंस गई। घटना के बाद संबंधित निर्माण एजेंसी हरकत में आई और क्षतिग्रस्त हिस्से को बैरिकेड कर मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है। सड़क धंसने से क्षेत्र में आवाजाही प्रभावित है और राहगीरों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने विभागीय अधिकारियों से दोषी एजेंसी पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं, इंजीनियरिंग टीम नुकसान का आकलन कर पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में जुटी है।

प्रदेश की कड़ाके की सर्दी के बीच 10 लाख बच्चों को नहीं मिले जूते-मोजे और स्वेटर के पैसेय इसलिए अटकी राशि

लखनऊ, (संवाददाता)। परिषदीय विद्यालयों में लंबी कवायद के बाद भी करीब दस लाख बच्चों को यूनिफार्म और जूते–मोजे की रकम का इंतजार है। हालांकि, इसमें से ज्यादातर का कारण इन बच्चों के अभिभावक ही हैं। कुछ अभिभावकों के आधार कार्ड ही नहीं बने हैं तो कुछ के आधार बैंक खाते से लिंक नहीं हैं। इससे डीबीटी में दिक्कत हो रही है। बेसिक शिक्षा विभाग अभियान चलाकर छूटे बच्चों को बैग, जूते–मोजे, स्वेटर व स्टेशनरी के लिए 1200 रुपये डीबीटी करने की कवायद कर रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में छात्र अभी वंचित हैं जबकि ठंड शुरू हो गई है। विभाग के मुताबिक लगभग 6.50 लाख अभिभावक ऐसे हैं जिनके आधार तो बने हैं लेकिन खाते से लिंक नहीं हैं। करीब 3.50 लाख अभिभावकों के आधार ही नहीं बने हैं। हालांकि, विभाग बीआरसी पर कैंप लगाकर अभिभावकों के आधार कार्ड बनवा रहा है।

मदरसे में गरजा बुलडोजर, अवैध निर्माण किए गए धराशायी जमीन कराई गई कब्जामुक्त

लखनऊ, (संवाददाता)। यूपी के सीतापुर में लहरपुर क्षेत्र में नवीन परती भूमि पर अवैध कब्जा

करके कराए गए पक्के व अस्थायी निर्माण पर बुधवार को बुलडोजर चला। प्रशासन ने अभियान चलाकर मदरसे और अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया। तहसीलदार के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के घेरे में इलाके के अलग–अलग गांवों में मदरसा समेत अन्य पक्के अवैध निर्माण आए। तहसील क्षेत्र के नेवादा गनेशपुर में गाटा संख्या 982 रकबा 0.028 हेक्टेयर के आंशिक भाग पर व गाटा संख्या 983ध्0.101 हेक्टेयर नवीन परती भूमि पर अवैध रूप से पक्के भवन में मदरसा संचालित किया जा रहा था। मदरसे का प्रबंधक रईस पुत्र मोहम्मद हुसैन व उसका सहयोगी सत्तार पुत्र मेंहदी हसन था। तहसील प्रशासन की टीम ने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया। वहीं, शेरपुर सरावां में गाटा संख्या 1030ध् 0.174 हेक्टेयर नवीन परती के आंशिक भाग पर अबरार पुत्र नजर मोहम्मद निवासी पंडित पुरवा ने भी पक्का निर्माण करा रखा था। न्यायालय के आदेश पर यह अवैध निर्माण भी ढहा दिया गया। तहसीलदार मनीष त्रिपाठी ने बताया कि नोटिस के बाद भी अवैध कब्जा न हटाए जाने पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई है।

सिर पर लटक रही मौत, फिर भी नीचे बना दिया आशियाना

लखनऊ, (संवाददाता)। फैजुल्लागंज द्वितीय के शिवनगर में रविवार को 33 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन से पतंग छुड़ाते वक्त 12 वर्षीय आर्यन के झुलसने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी में हाईटेंशन लाइन के नीचे ऐसी कई बस्तियां बसी हैं। ये बस्तियां अचानक नहीं बसीं। दो दशकों में प्रॉपर्टी डीलरों और बिजली इंजीनियरों की सांठगांठ से 11 और 33 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइनों के नीचे प्लॉट काटकर अनुमानित 10 हजार परिवारों को रोज मौत के साये में जीने के लिए मजबूर कर दिया गया है। पड़ताल में भरत नगर के निलेश कुमार मिश्र ने बताया कि प्रॉपर्टी डीलरों ने घर खरीदते समय भरोसा दिलाया था कि ओवरहेड बिजली की लाइनों को जल्द हटवा दिया जाएगा। इसके लिए एक लाख रुपये तक जमा कराए गए, लेकिन 15 वर्ष बीतने के बावजूद लाइन एक इंच भी नहीं हिली। फैजुल्लागंज निवासी सतीश भी बताते हैं कि जब हाईटेंशन लाइन के नीचे मकान बन रहे थे, उस वक्त बिजली इंजीनियरों ने आंखें मूंद रखी थीं। जब हादसा हुआ तो नोटिस उसी परिवार के घर पहुंचा, जिसे शुरुआत से प्रॉपर्टी डीलरों ने झांसा देकर ठगा था। मंगलवार को 12 वर्षीय आर्यन नबीकोटनंदना ट्रांसमिशन उपकेंद्र से निकलने वाली 33 केवी अहिबरनपुर लाइन से झुलसा था। इस लाइन के नीचे 700 से अधिक मकान बने हुए हैं। करीब आठ किमी के दायरे में हाईटेंशन लाइन इन घरों से सिर्फ एक–दो मीटर ऊपर गुजर रही है। इससे छत पर बैठना तो दूर, कपड़े तक नहीं सुखाए जा सकते। जरा सी चूक पर जान जाने का खतरा बना रहता है। चिनहट, भरवारा, गोमतीनगर विस्तार, निलमथा, तेलीबाग, साउथ सिटी, बिजनौर, नादरगंज, सरोजनीनगर, बंथरा, गेहरू, पारा, मोहान रोड, राजाजीपुरम, हरदोई रिंग रोड, बालागंज, आजादनगर, यासीनगंज, दुबग्गा, अंधे की चौकी हरदोई रोड, जेहटा, बरावन कला, आईआईएम रोड, फैजुल्लागंज, दाउदनगर, भरतनगर, श्रीनगर, मड़ियांव, नबीकोटनंदना, कुर्सी रोड, बेहटा, तकरोही सहित कई इलाकों में हाईटेंशन लाइनों के नीचे बड़ी बस्तियां मौजूद हैं।

संक्षिप्त खबरें

उप मुख्यमंत्री ने बदायूं मेडिकल कॉ लेज का निरीक्षण, निर्माण कार्यों में तेजी के निर्देश

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं का निरीक्षण किया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज और संबद्ध चिकित्सालय में चिकित्सा शिक्षकों की उपलब्धता, स्टाफ की स्थिति, शिक्षण व्यवस्था तथा निर्माण कार्यों की प्रगति की बारीकी से समीक्षा की।निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्थाओं यूपीआरएनएन, यूपी सिडको और सी एंड डी एस के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी लंबित निर्माण कार्य तय समयसीमा के भीतर पूर्ण किए जाएँ। उन्होंने कहा कि निर्माण से जुड़ी सभी समस्याओं का विवरण कॉलेज प्रशासन लिखित रूप में दे, ताकि उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही उन्होंने अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित रखने पर भी विशेष बल दिया।यूपी सिडको के अधिकारियों ने बताया कि नर्सिंग कॉलेज का निर्माण कार्य जनवरी 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा और फरवरी 2026 में उसे मेडिकल कॉलेज प्रशासन को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।प्रधानाचार्य अरुण कुमार ने उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि एनएमसी के मानकों के अनुरूप कॉलेज में चिकित्सा शिक्षकों और स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है। उन्होंने बताया कि शिक्षक एवं कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं और सभी कार्य समय पर पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।निरीक्षण के दौरान जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे।

टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट की तीसरी इकाई से यूपी को मिली नई ऊर्जा क्षमता

लखनऊ, (संवाददाता)। देश को ऊर्जा क्षेत्र में आज एक और बड़ी उपलब्धि मिली, जब 1000 मेगावाट क्षमता वाली देश की पहली वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज परियोजना, टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट की तीसरी यूनिट का वाणिज्यिक संचालन विधिवत शुरू किया गया। इस शुभारंभ में केंद्रीय विद्युत एवं आवास तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे। तीसरी यूनिट के संचालन से उत्तर प्रदेश की ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी और उपभोक्ताओं को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।टिहरी पीएसपी देश की प्रथम पंप स्टोरेज परियोजना है, जिसमें वेरिएबल स्पीड तकनीक का उपयोग किया गया है। यह तकनीक ऑफ–पीक घंटों में अतिरिक्त उत्पादित बिजली को स्टोर करके आवश्यकता के समय ग्रिड में 1000 मेगावाट तक की शक्ति उपलब्ध कराने में सक्षम है। परियोजना की पहली दो इकाइयाँ पहले ही सफलतापूर्वक ऊर्जा उत्पादन कर रही हैं, जबकि तीसरी इकाई के जुड़ने से इसकी प्रभावशीलता और बढ़ गई है। इस तकनीक के माध्यम से बिजली की मांग के अनुरूप रियल टाइम ऊर्जा स्टोरेज और रिलीज संभव होगा, जिससे राष्ट्रीय ग्रिड की स्थिरता और सुदृढ़ होगी तथा नवीकरणीय ऊर्जा को भी निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा।ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने तीसरी इकाई के सफल संचालन पर उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देते हुए ।

लखनऊ में वाहन चोरी गैंग का पर्दाफाश, तीन शातिर गिरफ्तारय चोरी का डाला

लखनऊ, (संवाददाता)। पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिमी जोन में कैसरबाग थाना पुलिस ने वाहन चोरी में सक्रिय एक गैंग का खुलासा करते हुए तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली सूचना पर की गई इस त्वरित कार्रवाई में पुलिस ने चोरी का एक डाला वाहन (ज।ज। ।ब्), तीन मोटरसाइकिलें और मुकदमे से संबंधित 29 हजार रुपये नकद बरामद किए। गिरफ्तारी की यह सफलता हाल के दिनों में बढ़ रही वाहन चोरी की घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई मानी जा रही है।यह पूरी कार्रवाई पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में, पश्चिमी जोन के पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त कैसरबाग तथा प्रभारी निरीक्षक कैसरबाग के नेतृत्व में

संचालित की गई। अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत मालदृ मुल्जिमान की तलाश में चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि चोरी की घटनाओं में संलिप्त तीन व्यक्ति बन्धा रोड क्षेत्र में मौजूद हैं। सूचना की पुष्टि होते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर तीनों को मौके पर ही पकड़ लिया।गिरफ्तार आरोपियों में पहला नाम मो. निजाम का है, जिसकी उम्र लगभग 33 वर्ष है। वह मूल रूप से बलरामपुर जिले के सादुल्लानगर थाना क्षेत्र के रहमतपुर गांव का निवासी है और वर्तमान में फैजुल्लागंज, नन्दा फोरम के पास रह रहा था। दूसरा अभियुक्त मो. हाशिम है, उम्र लगभग 40 वर्ष, जो फैजुल्लागंज जैनब मस्जिद के पास रहता है। तीसरा अभियुक्त अलीशाद है, उम्र लगभग 27 वर्ष, जो अली नगर खदरा, थाना मड़ियाव क्षेत्र में रहता है। पुलिस के अनुसार तीनों अभियुक्त संगठित रूप से वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे।इस कार्रवाई की शुरुआत उस रिपोर्ट से जुड़ी है, जिसमें 27 नवंबर 2025 को कैसरबाग थाना क्षेत्र के निवासी चन्द्रशेखार कुमार ने अपना छोटाहाथी चोरी होने की तहरीर दी थी। उसी मुकदमे (मु.अ.सं. 207ध् 2025) की जांच के दौरान पुलिस को लगातार अभियुक्तों की तलाश थी। बन्धा रोड पर पकड़े जाने के बाद तीनों की तलाशी में चोरी गया लोडर वाहन, तीन मोटरसाइकिलें और 29,000 रुपये नकद बरामद हुए। बरामद मोटरसाइकिलों में स्प्लेंडर प्लस, सुपर स्प्लेंडर और मोटरसाइकिल शामिल हैं। बरामदगी के आधार पर पुलिस ने अलग से मु.अ.सं. 211ध्2025 धारा 317(2) ठछै पंजीकृत किया और पूर्व मुकदमे में भी संबंधित धाराओं की बढ़ोत्तरी की गई।गिरफ्तारी की कार्रवाई रात लगभग 3रू30 बजे संपन्न हुई, जिसके बाद तीनों अभियुक्तों को उनके गिरफ्तारी कारणों और धाराओं से अवगत कराते हुए पुलिस हिरासत में लिया गया। अब उन्हें न्यायिक अभिरक्षा के लिए अदालत में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया जारी है।पुलिस जांच में यह सामने आया कि मो. निजाम एक संगठित अपराधी है और उसके खिलाफ कई जिलों में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। उसके आपराधिक इतिहास में वजीरगंज थाने में दो अलग–अलग मामलों में धारा 379ध् 411, मनकापुर (गोण्डा) में चोरी और धोखाधड़ी से संबंधित कई मामले, यूपी गैंगस्टर एक्ट का अभियोग तथा बलरामपुर जिले के रेहरा बाजार थाने में दर्ज एक मामला शामिल है।

टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट की तीसरी यूनिट शुरू

लखनऊ, (संवाददाता)। देश की पहली वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज परियोजनाकृ1000 मेगावाट टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट की तीसरी यूनिट का वाणिज्यिक संचालन मंगलवार को केंद्रीय विद्युत तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा की वर्चुअल उपस्थिति में शुरू हो गया। यह उपलब्धि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।तीसरी यूनिट के संचालन के साथ उत्तर प्रदेश को ऊर्जा आपूर्ति का एक मजबूत और स्थिर स्रोत हासिल हुआ है, जो भविष्य में उपभोक्ताओं को अधिक सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने में सहायक बनेगा। वेरिएबल स्पीड टेक्नोलॉजी से युक्त यह पंप स्टोरेज परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है, जो ऑफ–पीक समय में अतिरिक्त बिजली को संग्रहित कर ग्रिड को 1000 मेगावाट तक की पीकिंग पावर उपलब्ध कराने में सक्षम है।परियोजना की चार इकाइयों में से दो पहले ही सफलतापूर्वक वाणिज्यिक उत्पादन कर रही हैं। तीसरी इकाई के जुड़ने से परियोजना की क्षमता और अधिक सुदृढ़ हुई है। वेरिएबल स्पीड तकनीक के माध्यम से बिजली की मांग के अनुसार ऊर्जा का रीयल टाइम स्टोरेज और रिलीज संभव हो सकेगा, जिससे राष्ट्रीय ग्रिड पर लोड मैनेजमेंट की दक्षता बढ़ेगी। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड में सहजता से जोड़ने में भी मदद मिलेगी।ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने कहा कि यह क्षण उत्तर प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि तीसरी यूनिट के संचालन से प्राप्त बिजली में से 25 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश को मिलेगा, जिससे राज्य की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि परियोजना की।

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर मानवाधिकार

लखनऊ, (संवाददाता)। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यश विषय पर हुआ एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आ बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में दिनांक 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर मानवाधिकार विभाग एवंध् सेंटर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट लीगलध् स्टडीज के संयुक्त तत्वावधान में श्मानवाधिकाररू हमारी दैनिक आवश्यकताएँ – राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यश विषय पर एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री हेमचंद्र जी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त मंच पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन के चेयरपर्सन जस्टिस श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव , कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कार्यवाहक कुलपति प्रो. एस. विक्टर बाबू, फोरम फॉर ग्लोबल स्टडीज के फाउंडिंग डायरेक्टर एवं साउदर्न फ्रेडरल यूनिवर्सिटी, रशिया के विजिटिंग प्रोफेसर डॉ. संदीप त्रिपाठी, प्रो. प्रीति मिश्रा एवं मानवाधिकार विभाग के विभागाध्यक्ष और कार्यक्रम संयोजक प्रो. शशि कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं बाबासाहेब के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। विश्वविद्यालय कुलगीत गायन के पश्चात आयोजन समिति की ओर से अतिथियों एवं शिक्षकों को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत किया। सर्वप्रथम प्रो. प्रीति मिश्रा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत किया। साथ ही प्रो. शशि कुमार ने सभी को कार्यक्रम के उद्देश्य एवं रुपरेखा से अवगत कराया।मुख्य अतिथि एवं विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री हेमचंद्र जी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की वास्तविक प्रगति तभी संभव है, जब वहाँ सशक्त, पारदर्शी तथा सुशासन प्रदान करने वाली सरकार कार्यरत हो। सुशासन ही वह आधार है, जिस पर राष्ट्र विकास, सामाजिक न्याय और नागरिकों के कल्याण की संरचना खड़ी होती है। इसी के साथ भारतीय सभ्यता सदैव से व्यक्ति के नैतिक उत्थान, समानता और समाज में समरसता की स्थापना पर बल देती आई है। उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा प्रज्ञा, शील और करुणा जैसे गुणों को मानव जीवन की आधारशिला मानती है, क्योंकि इन्हीं गुणों के माध्यम से समाज में सौहार्द, सहयोग और संतुलन की भावना विकसित होती है। व्यक्ति की उन्नति केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि उसकी सद्बुद्धि, उत्तरदायित्व–बोध और मूल्यबद्ध आचरण से निर्धारित होती है। दूसरी ओर, मानवाधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और अनिवार्य हैं और केवल कानूनी दस्तावेजों तक सीमित न रहकर वैश्विक स्तर पर मानव गरिमा की रक्षा का आधार बनते हैं। अतः सुशासन, नैतिकता, समानता और मानवाधिकार ये सभी मिलकर एक ऐसे प्रगतिशील, शांतिपूर्ण और मानवीय समाज की रचना करते हैं जहाँ व्यक्ति और राष्ट्र, दोनों का संतुलित विकास संभव हो पाता है।कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रो. विक्टर बाबू ने मानवाधिकार दिवस के अवसर पर कहा कि मानवाधिकार केवल अधिकारों की सूची नहीं, बल्कि मानवता को उन्नत करने का वह नैतिक आधार है, जो प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान, स्वतंत्रता और न्याय के साथ जीने का अवसर देता है। उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में यह और भी आवश्यक हो गया है कि हम विविधताओं का सम्मान करें, संवेदनशीलता को बढ़ाएँ और समाज में सहभागिता की भावना विकसित करें। मानवाधिकार तभी सार्थक होते हैं जब हम उन्हें व्यवहार में उतारें और हर व्यक्ति के जीवन में समान अवसर एवं गरिमा सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि मानवाधिकार दिवस को केवल उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि मानव कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः सुदृढ़ करने के अवसर के रूप में देखें।विशिष्ट अतिथि एवं उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन के चेयरपर्सन जस्टिस श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने अपने विचार रखते हुए कहा कि मानवाधिकार किसी भी सभ्य समाज की प्रगति का मूल आधार हैं। मानवाधिकार न केवल व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि उसे अपनी क्षमताओं का विकास करने, सामाजिक जीवन में सक्रिय सहभागिता निभाने और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करते हैं। जिस समाज में मानवाधिकारों की समझ और स्वीकृति प्रबल होती है, वहाँ सामाजिक सद्भाव, विश्वास और सहयोग स्वतः विकसित होता है।

31 मार्च तक 8.46 लाख से तैयार होंगे अन्नपूर्णा मॉडल स्टोर

(राजन तिवारी संवाददाता अयोध्या धाम)

अयोध्या।डबल इंजन की सरकार के सुशासन और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रम में अयोध्या जिले में उचित दर की दुकानों को आधुनिक स्वरूप देने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिले में अब तक 62 अन्नपूर्णा मॉडल स्टोर पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, जबकि मार्च 2026 तक 19 और नए स्टोर उपभोक्ताओं को समर्पित कर दिए जाएंगे।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तेजी से बन रहे इन मॉडल स्टोर ने ग्रामीण क्षेत्रों में राशन वितरण को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया है। इन स्टोरों के जरिए राशन कार्ड धारकों को न केवल सस्ता अनाज मिलेगा, बल्कि साफ–सुथरे वातावरण में खाद्यान्न के साथ–साथ दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुएं भी एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी।जिला आपूर्ति अधिकारी बृजेश कुमार मिश्रा ने बताया

कि अयोध्या जिले में कुल 102 अन्नपूर्णा मॉडल स्टोर बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। इसमें 75 स्टोर मनरेगा कन्वर्जेंस के तहत तथा 27 स्टोर विभागीय बजट से बनाए जाने थे। शासन ने अभी तक विभागीय बजट से 19 स्टोर की स्वीकृति प्रदान की है। इनमें 13 स्टोर नगर क्षेत्र में तथा 6 स्टोर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सभी 19 स्टोर 31 मार्च 2026 तक पूर्ण करके उपभोक्ताओं को सौंप दिए जाएंगे।जिला आपूर्ति अधिकारी डॉ बृजेश मिश्रा ने बताया कि कार्यदाई संस्था का चयन पूरा हो चुका है। मॉडल स्टोर के लिए बजट की पहली किस्त 4 लाख 23 हजार रुपये प्राप्त हो चुकी है। प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत 8 लाख 46 हजार रुपये रखी गई है। शेष राशि कार्य प्रगति के साथ जारी की जाएगी। तय समय–सीमा से पहले सभी स्टोर तैयार कर लिए जाएंगे।

अन्नपूर्णा मॉडल स्टोर योजना के तहत राशन की दुकानों को मिनी मार्ट की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। इन स्टोरों में राशन के साथ दाल, तेल, नमकीन, बिस्किट, साबुन, सरफ, चाय पत्ती जैसी दैनिक जरूरत की वस्तुएं भी बाजार मूल्य से कम दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। स्टोर में बैठने की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ेगी।

स्कूल रेडीनेस फेज–1 के प्रथम बैच के प्रशिक्षण का डॉ. गोरखनाथ पटेल ने किया शुभारंभ

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ पटेल ने राजा डी. एम. सिया इंटर कॉलेज के सभागार में स्कूल रेडीनेस फेज–1 प्रशिक्षण कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया। कार्यक्रम दो बैचों में आयोजित होना है, जिसमें प्रथम बैच के तहत मुफ्तीगंज, मुंगराबादशाहपुर, नगर क्षेत्र, रामनगर, रामपुर, शाहगंज, सिकरारा, सिरकोनी, सुतौना कला एवं सुजानगंज विकासखंडों के नोडल शिक्षण संकुल, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर तथा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां शामिल हुईं। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए डॉ. गोरखनाथ पटेल ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप परिषदीय विद्यालयों में बाल वाटिका स्तर से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की शुरुआत की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक संचालित होने वाला यह फेज बच्चों को प्री–प्राइमरी शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। डॉ. गोरखनाथ पटेल ने प्रेरित करते हुए कहा, "इतिहास गवाह है कि जिस देश के नौनिहाल बचपन से ही शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ जाते हैं, उसे विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता।" कार्यक्रम में जिला समन्वयक प्रशिक्षण विशाल कुमार ने मुख्य अतिथि का बुके एवं अंग–वस्त्र से सम्मान किया। प्रशिक्षण सत्र का संचालन डायट प्रवक्ता अमित कुमार, एसआरजी डॉ. कमलेश एवं अजय कुमार मौर्य ने किया।

संक्षिप्त खबरें

किसान पाठशाला अभियान आज से

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर उप कृषि निदेशक ने अवगत कराया है कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है। रबी अभियान के लिए निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति के लिए 13 दिसम्बर 2025 से 29 दिसम्बर 2025 तक ग्राम पंचायत स्तरीय रबी गोष्ठीधकिसान पाठशाला अभियान चलेगा। उप कृषि निदेशक हिमांशु पांडेय ने बताया कि अभियान का रोस्टर जिलाधिकारी डा. दिनेश चन्द्र द्वारा जारी कर संबंधित अधिकारियों को प्रभावी तरीके से कार्यक्रम करने के निर्देश दिए गये है। उन्होंने बताया कि जनपद मे कुल 625 ग्राम पंचायतों में दो दिवसीय पाठशाला आयोजित होगी, जिनमे कृषि वैज्ञानिक, कृषि एवं संबंधित विभागों के अधिकारीध्कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है, जो रोस्टर के अनुसार निर्धारित गांवो में दो दिनों तक कार्यक्रम करेगी, जो उन्नति तकनीकीयो एवं योजनाओं से जागरूक किया जाएगा ताकि किसान कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त कर अपनी समृद्धि करते हुए कृषि का सतत विकास कर सकते है।

'13 दिसम्बर 2025 (दिन शनिवार) को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन'

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं माननीय जनपद न्यायाधीशध्अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर श्री सुशील कुमार शशि के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर के तत्वावधान में दिनांक 13 दिसम्बर 2025 दिन शनिवार को प्रातः 10:00 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर, जौनपुर एवं समस्त तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में ई–चालान व आर्बिट्रेशन के निष्पादन वाद, प्री–लिटिगेशन (वाद–पूर्व) स्तर पर पारिवारिकध्दाम्पत्य विवाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम वाद, धन वसूली वाद, श्रम एवं सेवायोजन विवाद, विद्युत, जल बिल एवं अन्य प्रकार के बिलों के भुगतानों के विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), भरण–पोषण वाद तथा अन्य प्रकार के आपराधिक शमनीय व सिविल वाद तथा विभिन्न न्यायालयों में लम्बित आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम वाद, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकायें, श्रम एवं सेवायोजन विवाद, विद्युत, जलकर बिल एवं अन्य प्रकार के बिलों के भुगतानों के विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित) पारिवारिक वाद (विवाह विच्छेद सम्बन्धित वादों को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा में वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्ति परिलाभों से सम्बन्धित विवाद, आपसी सुलह–समझौतें के आधार पर निस्तारित होने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जायेगा। अतः वादकारी गण एवं अधिवक्ता गण अपने–अपने वादों से सम्बन्धित न्यायालयों में सम्पर्क स्थापित कर वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु संदर्भित करायें एवं अधिकतम वादों का निस्तारण कराकर लोक अदालत का लाभ उठायें।

इमरजेंसी सहित ओपीडी में एमआर के आने से हो रहा है मरीजों का इलाज प्रभावित

अयोध्या। जिला पुरुष चिकित्सालय में इस समय मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव परिसर के अंदर काफी संख्या मे सुबह से दिखाई देने लगते हैं और जिला चिकित्सालय के बंद होने के बाद भी दिखाई पड़ते हैं।जो सुबह 10रू00 से जिला पुरुष चिकित्सालय के इमरजेंसी कक्ष के अलावा सभी ओपीडी कक्ष ओपीडी बंद होने के बावजूद भी बैठे रहते हैं।जिसके चलते वहां पर तैनात चिकित्सकों द्वारा मरीज को दिखाने में परेशानी होती है। शुक्रवार को दोपहर करीब 11रू30 के आसपास चाहे चर्म रोग, हो अस्थि रोग हो या फिर इमरजेंसी हो वहां पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपने–अपने दावों के बारे में फोल्डर के माध्यम से चिकित्सकों को बताते नजर आए। इस मौके पर वहां पर मौजूद मरीजों ने बताया कि हम लोग काफी समय से यहां पर बैठे हुए हैं जिसके चलते अधिकतर ओपीडी में लंबी लाइन भी लगी हुई है परंतु इन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के चलते हम सभी का इलाज समय से नहीं हो पा रहा है। इन मरीजों का यह भी कहना था कि यहां पर तैनात चिकित्सकों तथा इनके

बीच चंद रुपये के चलते हम लोगों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर दूर दराज से आने वाले मरीजों तथा उनके परिजनों का कहना था कि समय से इलाज न होने के चलते हम लोगों की यहां तक सवारी भी छूट जाती है परंतु इस गंभीर समस्या पर इससे संबंधित अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं।इस संबंध में जिला पुरुष चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश सिंह ने बताया कि यह मामला बहुत ही गंभीर है उन्होंने कहा कि सिर्फ 2रू00 बजे तक ही नहीं बल्कि जिला पुरुष चिकित्सालय परिसर में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का प्रवेश पूर्णतया वर्जित रहेगा हां इतना जरूर है कि अगर वह किसी अन्य काम के लिए आते हैं जैसे अपना या अपने सगे संबंधियों का इलाज करने के लिए आते हैं तो ठीक है और अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के हैसियत से आते हैं तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी और सीख रही इसके खिलाफ सेकंड चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा।

जिला दिव्यांग जन कल्याण अधिकारी जिला चिकित्सा जाकर दिव्यांग जनो की सुनी समस्याए

अयोध्या। शुक्रवार को जिला दिव्यांग जन कल्याण अधिकारी चंद्रेश त्रिपाठी ने जिला चिकित्सालय परिसर में स्थित जिला दिव्यांग कल्याण बोर्ड का निरीक्षण किया।इस दौरान उन्होंने वहां पर आये काफी संख्या मे दिव्यांग जनो से बातचीत किया।वहाँ पर आये दिव्यांग जनो से उन्होंने कहा कि अगर आप सभी को किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो वे सीधे विकास भवन स्थित उनके कार्यालय पर आकर अपनी समस्याओं को रख सकते हैं।इस मौके पर वहां पर दूर दराज से आए कई दिव्यांग जनों ने अपनी अपनी समस्याओं को भी रखा।जिसे दूर करने के लिए उन्होंने वहां पर मौजूद अधिकारियों व कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए।उन्होंने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य यहां पर आने के लिए जिले में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोलने के लिए जिला चिकित्सालय के साथ–साथ मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर पर जाकर जमीन देखने के अलावा बिल्डिंग को देखना था।इस सिलसिले में वे आज मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर तथा जिला चिकित्सालय परिसर में स्थित भवन व जमीन को देखने आए थे।इस मौके पर प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक जिला पुरुष चिकित्सालय डॉ राजेश कुमार सिंह से हुई बातचीत में यह लगभग तय हो चुका है कि यहां की बिल्डिंग काफी पुरानी है और लगभग 5 से 6 कमरे जो कि इस केंद्र को खोलने के लिए चाहिए जो कि नहीं है वही 4000 स्क्वायर फीट जमीन भी परिसर में नहीं मौजूद है। देखा जाए तो लगभग लगभग दर्शन नगर स्थित मेडिकल कॉलेज में इस केंद्र को खोले जाने की पूरी तरह से विभाग द्वारा सहमत बन चुकी है और तीन दिन के अंदर इसकी सूचना मुख्यालय को भेज दी जाएगी।

संक्षिप्त खबरें

मंडलायुक्त के आदेश पर पंचायत प्रशासन हरकत में आकर कस्बे में अलाव जलवाने की प्रक्रिया हुई शुरु

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।नगर पंचायत मे अलाव जलवाने की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई।इस बार कस्बे के बारहों वार्डो तथा मुख्य मार्ग के चौराहों पर अलाव कौन जलवायेगा,इसका पता 18 दिसंबर को नगर पंचायत कार्यालय परिसर में होने वाले बोली पर लगेगा।फिलहाल राहगीरों एवं नगर पंचायत वासियों को अलाव तापने के लिए अभी एक सप्ताह का इंतजार और करना पड़ेगा।मालूम हो कि दिसंबर माह में बढ़ रही ठंड की विभीषिका को देखते हुए गोसाईगंज रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन,तेलियागढ़,भीटी चौराहा,(कटरा)बस स्टॉप तथा अस्पताल परिसर में अलाव जलवाने तथा गरीबों मजलूमों में कंबल वितरण किए जाने की मांग गोसाईगंज नगर पंचायत की सभासद एवं जय बाबा अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति रजि0 की अध्यक्ष श्रीमती आरती जयसवाल ने नगर पंचायत प्रशासन के जिम्मेदारानो को बीते 01 दिसंबर को मांग पत्र देकर की थी।लेकिन कुंभकर्णी निद्रा में मगन पंचायत प्रशासन अलाव जलवाने में हीला हवाली करता रहा तो सभासद श्रीमती जायसवाल ने बीते 9 दिसंबर को मंडलायुक्त को एक मांग पत्र देकर नगर पंचायत प्रशासन को निर्देशित कर जल्द से अलाव जलवाने एवं कंबल वितरण किए जाने की मांग की।ईओ सीमा राय ने बताया कि कस्बे में 45 दिनों तक अलाव जलवाने के लिए 18 दिसंबर को निविदा खोली जाएगी।

पेसारा में सोसाइटी की जर्जर बिल्डिंग में हो रहा यूरिया वितरण

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर ,11 दिसंबर। एक तरफ जहां सरकार किसानों को लेकर गंभीर है उन्हें हर तरह कीसुवधा उपलब्ध करा रही है तो वही जिले जिले के मुफ्तीगंज ब्लॉक के पेसारा सोसाइटी की जर्जर बिल्डिंग में यूरिया का वितरण किया जा रहा है।जिसको लेकर विभागीय मंत्री अधिकारी संजीदा नहीं दिख रहे हैं।विभाग के अधिकारयों को इस भवन में किसी हादसे का इंतजार है।तब इनकी तंद्रा खुलेगी जब किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। हालात यह है कि किसान खाद लेने की लिए लाइन में लगने से भी डर रहे हैं। यहां कभी भी हादसा हो सकता है। सोसाइटी सचिव यादवेंद्र सिंह का कहना है कि विभाग के अधिकारियों से कई बार बिल्डिंग के बारे में कहा गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

किसान कड़ाके की सर्दी में पहुंच गए हैं। किसानों का कहना है कि यूरिया लेने में कोई परेशानी नहीं है। खाद आसानी से मिल जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि खाद्य आसानी से मिल जाती है लेकिन बिल्डिंग बहुत ही जर्जर है कभी भी हादसा हो सकता है। दूसरे किसानों का भी साफ तौर पर कहना है कि बिल्डिंग बहुत ही जर्जर है दूर से ही लाइन लगाकर सामान लेना पड़ता है सामान आसानी से मिल जाता है। ग्रामीण का कहना है की बिल्डिंग बहुत ही जर्जर है खाद तो दे देते हैं लेकिन बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है।

कुमारगंज पुलिस ने स्कूल में चोरी करने वाले तीन अभियुक्तों को चोरी के सामान सहित किया गिरफ्तार

(राजन तिवारी संवाददाता अयोध्या धाम)

अयोध्या।शुक्रवार को कुमारगंज पुलिस ने स्कूल में चोरी करने वाले तीन आरोपियों को चोरी के समान सहित गिरफ्तार किया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष कुमारगंज ओमप्रकाश ने बताया कि एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बलवंत चौधरी के निर्देश पर सीओ मिल्कीपुर अजय कुमार की देखरेख में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कुमारगंज पुलिस छापामारी अभियान कर रही है। इसी अभियान के तहत शुक्रवार को

उनके नेतृत्व में गठित टीम में शामिल चौकी प्रभारी देवगांव थाना कुमारगंज अशोक कुमार पाठक ने ग्राम घोडवल स्थित बाग से गिरफ्तार किया। बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मोहित पुत्र जुगनु पासी निवासी ग्राम पालपुर थाना कुमारगंज अयोध्या हाल पता–ग्राम फत्तेपुर थाना हलियापुर सुल्तानपुर,अरविन्द कुमार पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम रामपुर बबुआन थाना हलियापुर जनपद सुल्तानपुर तथा

प्रेम कुमार पुत्र हृदयराम निवासी ग्राम रामपुर बबुआन थाना हलियापुर जनपद सुल्तानपुर के रुप मे हुई है।

थानाध्यक्ष कुमारगंज ओम प्रकाश के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में अभियुक्तो ने बताया गया कि वे दिन में घूम फिर कर स्कूल की रेकी करते है, उसके बाद रात में उस स्कूल में आकर के लोहे की आरी ब्लेड एवं लोहे की सरिया से ताला तोडते है तथा एक आदमी उनमे से आने जाने वाले पर निगरानी करता रहता है, दो आदमी अन्दर चोरी करते है।बताया कि अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

कौशलपुरी कॉलोनी में जल्द होगा जल निकासी का प्रबंध, टूटी नालियों की होगी मरम्मत – महापौर

(राजन तिवारी संवाददाता अयोध्या धाम)

अयोध्या। कौशलपुरी कॉलोनी को जल्द ही जल भराव की समस्या से निजात मिलेगी। महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने श्नगर की सरकार आपके द्वारश अभियान के तहत नगर आयुक्त श्री जयेंद्र कुमार के साथ जायज लिया। उन्होंने विशेष अभियान के तहत नाले की सफाई कर कर जल निकासी का स्थाई समाधान ढूंढने तथा तब तक पंप लगाकर जल निकासी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।सुबह 8:00 बजे महापौर एवं नगर आयुक्त सब्जी मंडी के पीछे निराला नगर के समोसा गली पहुंचे। यहां क्षेत्रीय पार्षद धर्मवीर, अपर आयुक्त डॉ. नागेंद्र नाथ एवं भारत भार्गव, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आरएम शुक्ल, निर्माण विभाग के सहायक अभियंता भारत सिंह वर्मा समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे।मोड़ पर सफाई कार्य चल रहा था, लेकिन जल भराव की समस्या देखकर महापौर ने नाराजगी जताई और रायबरेली अंडरपास की ओर जाने वाले नाले की सफाई कराकर जल निकासी सुनिश्चित करने का निर्देश

जोनल अधिकारी कौशलपुरी को दिया। थोड़ा आगे बढ़ने पर हनुमान मंदिर के पास उन्होंने खुली नाली देखकर पटिया रखने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सड़क की दूसरी ओर जल भराव को देखकर नाली निर्माण कराने और क्रॉसिंग बनवाने को कहा।महापौर ने डॉ. आरके सिंह के बगल गली को ऊंचा करने तथा ओपीएस इंटर कॉलेज के सामने लाइट लगवाने का निर्देश दिया। यहां लाइट की मांग स्थानीय निवासी अमर सिंह ने उनके सामने रखी। खोजनपुर पहुंचने पर जल भराव की समस्या दिखाई पड़ी। उन्होंने तालाब पैमाइश कराकर सफाई करने, गहराई बढ़ाने तथा रेलिंग लगाने का निर्देश दिया। नगर आयुक्त ने यहां कूड़ा फेंकने से मना करने के लिए बोर्ड लगाने को कहा।थोड़ा आगे बढ़ने पर नाली की सफाई न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने भाजपा नेता गोकुल समेत स्थानीय लोगों की मांग पर नाली बनवाने का वादा किया। खोजनपुर की गली में बिजली के तार लटके थे। इस पर नगर आयुक्त ने वहां तीन पोल लगाकर तारों को ऊंचा करने का निर्देश दिया।उन्होंने विष्णुपुरी कॉलोनी में प्रकाश व्यवस्था सुधार करने के लिए खराब लाइट को बदलने तथा जरूरत के मुताबिक नई लाइट लगाने के साथ ही टूटी नालियों की मरम्मत करने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। डॉ. रमापति मिश्र के घर के सामने पार्क में ओपन जिम लगाने तथा नालियों की मरम्मत कराने को कहा।नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश पांडेय ने बताया कि निरीक्षण दो घंटे से अधिक समय तक चला।इस दौरान पूर्व उपसभापति जय नारायण सिंह रिंकू, भाजपा नेता वरुण चौधरी, इंजीनियर रवि तिवारी, मंडल मंत्री वीरेंद्र वर्मा, श्रीप्रकाश पाठक, देवमणि द्विवेदी, अमर सिंह आदि थे।

जौनपुर में केदार फार्मा से जुड़े व्यक्ति के घर ईडी की छापेमारी कोडीन कफ सिरप की अवैध बिलिंग मामले में ईडी ने की कार्रवाई

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर ,11 दिसंबर ।शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केदार फार्मा से जुड़े एक व्यक्ति के घर पर छापेमारी की। यह कार्रवाई कोडीन कफ सिरप की अवैध बिलिंग से जुड़े मामले में की गई है। ईडी की टीम ने सीएमओ कार्यालय के सामने स्थित अमर पांडेय के आवास पर दबिश दी। यह मामला उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोडीन कफ सिरप की बड़ी मात्रा में बरामदगी के बाद शुरू हुई जांच से संबंधित है। इस जांच की बात बीते 20 नवंबर को सामने आई थी। नवंबर में हुई छापेमारी के दौरान, जिले की कई मेडिकल एजेंसियों से प्रतिबंधित सिरप की बड़ी खेप मिली थी। निगम मेडिकल एजेंसीज, ओलंदगंज के मालिक देवेश कुमार दुबे के यहां से 21 हजार बोतलें, एसएन मेडिकल एजेंसी, मुफ्ती मोहल्ला की मालिक महरून निशा के यहां से 18 हजार बोतलें और केदार मेडिकल एजेंसी, उदपुर, नौपेडवा से सर्वाधिक 62,250 बोतलें जब्त की गई थीं। इस मामले में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय ने बताया था कि कुल 15 फर्मों के नाम सामने आए हैं। इन सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई थी। इस खेल में शहर कोतवाली क्षेत्र के पूर्वांचल एसोसिएट के मालिक अंकित कुमार श्रीवास्तव का नाम भी शामिल था, जिनकी फर्म से 4 लाख बोतल सिरप की बिलिंग का खुलासा हुआ था। इसी क्रम में पूर्वांचल फार्मा रासमंडल में अंकित श्रीवास्तव आरोपित के साथ पार्टनर के रूप में काम करने वाले विकाश सिंह नारवे पुत्र नरसिंह नारवे कोतवाली थाना अंतर्गत वाजिदपुर उत्तरी निवासी के घर ईडी की टीम ने छापेमारी किया है।इसी क्रम में टोयटा गाड़ी की ऑफिस सिपाह में भी छापेमारी किया है।संजय श्रीवास्तव से पूछताछ किया है। प्रदेश के कई जिलों में ऐसे नाम सामने आने के बाद ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। जिले में ईडी की इस कार्रवाई से अन्य कोडीन सिरप कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।